**जनजातीय युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिशीलता को बढ़ावा देने के लिए रांची में शुरू की गई ग्रामीण उद्यमी परियोजना, कुशल भारत मिशन को बढ़ावा देती है**

- कौशलीकरण समृद्धि का पासपोर्ट है: श्री राजीव चंद्रशेखर, एमएसडीई राज्यमंत्री
- श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर गांवों, आत्मनिर्भर कस्बों और आत्मनिर्भर जिलों से होकर जाएगा - श्री राजीव चंद्रशेखर
- परियोजना का दूसरा चरण रांची, झारखंड में जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया

**रांची, 20 अगस्त, 2022:** जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ भागीदारी में आज ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल के अंतर्गत, भारत के युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करने और उनकी आजीविका को सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करने का प्रयास है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों की कार्यबल में भागीदारी पर बल दिया है, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में शामिल किया है।

माननीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्य मंत्री, ने भव्य सभा को वर्चुअली संबोधित किया और श्री बिश्वेश्वर टुडू, जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्यमंत्री ने अपने उत्साहजनक संबोधन से दर्शकों को प्रेरित किया।

इस कार्यक्रम में प्रमुख गण्यमान्य व्यक्तियों, श्री वी. सतीश, महामंत्री, राष्ट्रीय सह-संगठन, श्री समीर उरांव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनसूचित जनजातीय मोर्चा और राज्यसभा संसद तथा श्री शिवशंकर उरांव, विधायक, गुमला, झारखंड की उपस्थिति देखी गई।

ग्रामीण उद्यमी एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्त-पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में कार्यान्वित की जा रही है। इस अवधारणा को माननीय राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), एसडीई और जनजातीय सांसदों द्वारा विस्तृत विवेचन किया गया था।

इस अवसर पर वक्तव्य देते हुए **माननीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा** ने कहा, “हमारा पूरा ध्यान जनजातीय आबादी के लिए स्थायी आजीविका को सुदृढ़ करने पर है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए

85,000 करोड़ के बजट का अनुमोदन दिया है। स्वामित्व बढ़ाने की भी सख्त आवश्यकता है ताकि ऐसी स्कीमों और पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा हो। जनजातीय युवाओं में पर्याप्त सामर्थ्य और क्षमता है, कि हमें केवल इतना करना है कि इन्हें सही अवसर प्रदान करें ताकि वे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकें। आज का शुभारंभ इस दिशा में एक कदम है, मुझे विश्वास है कि ग्रामीण उद्यमी परियोजना झारखंड के जनजातीय समुदायों के लिए दूरगामी साबित होगी और उन्हें स्वावलंबी होने का अवसर प्रदान करेगी। मैं अपने युवाओं को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपने संबंद्ध ग्राम पंचायतों, गांवों और ब्लॉकों से इन पहलों को आप तक लाने और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने का आग्रह करें।"

**कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर** ने कहा, "हमने हाल ही में भारत के समृद्ध अतीत का सम्मान करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और 25 वर्षों के लिए नए भारत के लिए एक विज़न अमृत काल के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। यह नया भारत, भारत के युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। हम सभी ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखा, लेकिन इस गंभीर स्थिति पर भारत की जीत का भी अनुभव किया और हमारे प्रयासों को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर गांवों, आत्मनिर्भर कस्बों और आत्मनिर्भर जिलों से होकर जाएगा। इसलिए, हमारे जनजातीय समुदाय भारत के आर्थिक विकास को गति देने के हमारे प्रयासों वरीयता देते हैं। मुझे आशा है कि ग्रामीण उद्यमी परियोजना ने मध्य प्रदेश में जो सफलता प्राप्त की है, उसे झारखंड में भी वही स्वीकृति मिलेगी क्योंकि कौशलीकरण किसी भी क्षेत्र की समृद्धि का पासपोर्ट है।"

**जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू** ने व्यक्त किया, यदि हम गांवों के विकास में निवेश करते हैं, तो शहरों का विकास होगा और शहरों का विकास होगा तो, एक राष्ट्र विकसित हो सकता है और इसका एक प्रमुख घटक हमारे जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है ताकि उनके विकास के लिए कई संभावनाएं खुल सकें। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जनजातीय क्षेत्रों की समावेशिता, वित्तीय विकास पर भी फोकस किया है और निश्चिततः, ग्रामीण उद्यमी परियोजना हमारी जनजातीय आबादी को आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करेगी। भारत के आर्थिक इंजन को गति प्रदान करने के लिए कई स्कीम और प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

प्रशिक्षण के पहले चरण में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से उम्मीदवारों को जुटाया गया था। चूंकि उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों से जुटाए गए थे, इसलिए उम्मीदवारों को परिवहन, बोर्डिंग और आवास प्रदान किया गया ताकि वे संसाधनों की कमी के कारण सीखने के अवसर से न चूकें।

भोपाल, मध्य प्रदेश में, मई, 2022 के महीने में सात बैचों में 157 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शुरू हुआ और लगभग 133 उम्मीदवारों ने 27 जून, 2022 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। रांची में आज शुरू किए गए प्रायोगिक परियोजना के दूसरे चरण का क्रियान्वयन युवा विकास सोसायटी द्वारा रांची में सेवा भारती केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। एमएसडीई के तत्वावधान में एनएसडीसी ने सेवा भारती केंद्र कौशल विकास केंद्र में क्षेत्र  कौशल परिषदों (एसएससी) के माध्यम से प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की स्थापना में सहायता की है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण निम्नलिखित जॉब रोलों में आयोजित किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हैं।

- इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन
- नलसाजी और चिनाई
- 2-व्हीलर मरम्मत और रख-रखाव
- ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईज़
- फार्म मशीनीकरण

सांसद परिसंकुल योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी योजना कार्यान्वित की गई है। जनवरी 2020 में जनजातीय समुदायों के उत्थान पर चर्चा करने के लिए माननीय सांसदों का दो दिवसीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों और सरकारी संगठनों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातीय संगठनों ने 'संसदीय एसटी क्लस्टर विकास परियोजना' की मांग की, जिसे शुरू कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत भारत के 15 राज्यों में 49 समूहों का चयन लोकसभा और राज्यसभा के 40 जनजातीय सांसदों द्वारा किया गया है। उनके नेतृत्व में इस स्कीम को संबंधित क्लस्टरों में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में सांसदों द्वारा एक विकास सहयोगी की नियुक्ति की जाती है।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है:

- ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- स्थानीय अवसरों की कमी के कारण मजबूरन प्रवास को कम करना
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

कौशल और शिक्षा की कमी के कारण, राष्ट्रीय औसत की तुलना में संगठित क्षेत्रों का जनजातीय आजीविका में बहुत कम योगदान है। इसलिए, ग्रामीण उद्यमी परियोजना जैसी पहल उनकी बेहतरी के लिए और उनकी आजीविका सृजन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।